(2010) 10 एस.सी.आर. 598

देहल सिंह

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1215/2005 आदि)

31 अगस्त, 2010

[हरजीत सिंह बेदी और चंद्रमौली के.आर. प्रसाद, जे. जे.]

स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985:

धारा 20-आरोपी के पास से बड़ी मात्रा में चरस पाया गया-दोषसिद्धि-याचिका कि प्रयोगशाला में वजन करने पर नमूनों के वजन में 15 ग्राम का अन्तर, अभियोजन मामले की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है-अभिनिर्धारण: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वजन मापने का पैमाना और किसी किराये की दुकान के वजन अधिकृत अधिकारी द्वारा उपयोग किया जाता था और प्रयोगशाला में प्रतिबंधित पदार्थ का वजन सटीक पैमाने के साथ मापा जाता था, वजन में छोटा अंतर इसका महत्व खो देता है।

एसएस 20, 35 और 54-'सचेत कब्जा'-उपधारणा-उपधारणा के खण्डन करने का भार-अभिनिर्धारण न्यायालय सचेत कब्जे के संबंध में

कब्जा मान सकता है-यह उस व्यक्ति के लिए है जो यह स्थापित करने का दावा करता है कि वह सचेत कब्जा नहीं था।

धारा 50 – गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें छिपाई गई भारी मात्रा में चरस बरामद हुई-दलील यह है कि अभियुक्तों को राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी के विकल्प के उनके अधिकार के बारे में अवगत नहीं करवाया गया था-अभिनिधार्रित धारा 50 में यह आकर्षित होते हैं कि-चूंकि वाहन से वसूल की गई थी इसलिए धारा 50 के प्रावधानो का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था।

धारा 50-किसी राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष खोजे जाने वाला विकल्प अभिनिर्धारित-चुनने का विकल्प दिया गया। एक अभियुक्त को जब चुनने का अधिकार है तो यह स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अधिकार का संचार है-तथ्यों पर, हालांकि धारा 50 का प्रावधान आकर्षित नहीं होता, अभियुक्ता को उनके अधिकार से अवगत करवाया गया था इसलिए, प्रावधान का अनुपालन किया गया था।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 313 और 315-अभिकथन अन्तर्गत धारा 313-प्रकृति और उद्देश्य-समझाया गया-अभिनिर्धारणः आरोपी की दलील की उसने वाहन में लिफ्ट ली थी, जिसमें से भारी मात्रा में 'चरस' बरामद किया गया था, केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि धारा 313 के

तहत उनके बयान के बारे में, जबकि न तो उन्होंने धारा 315 के तहत जांच की और न ही बचाव में किसी अन्य व्यक्ति से-साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 3 के तहत

एक गुप्त सूचना प्राप्त होने पर पीडब्लू-16 (स्टेशन हाउस ऑफिसर) ने हिमाचल प्रदेश में एक राजमार्ग पर एक कार को रोका, जिसमें चालक (ए-1) और गोवा का निवासी एक अन्य व्यक्ति बैठा था। चालक एक मैकेनिक (पीडब्लू-3) की मदद से कार की तलाशी ली गई और कार की ढालों और दरवाजों के बीच छुपाया गया 27 किलोग्राम और 800 ग्राम 'चरस', बरामद किया गया। रासायनिक परीक्षक द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ के नमूनों की चरस के रूप में पुष्टि की गई थी। विचारण न्यायालय ने दोनों आरोपियों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें 10 साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने उनकी अपील खारिज कर दी।

अभियुक्त द्वारा दायर तत्काल अपील में, यह तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रत्येक 50 ग्राम के नमूने लिए गए और फाॅरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे गए, लेकिन प्रयोगशाला में प्राप्त नमूनों का शुद्ध वजन 65.5606 ग्राम था, और विसंगति वजन में पुर्नप्राप्ति कार्रवाई की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा होता है। परिणामस्वरूप

आगे अभियोंजन मामले की विश्वसनीयता; यद्यपि अभियुक्तों को राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्हें इस संबंध में उनके अधिकार से अवगत नहीं करवाया गया था और इसलिए, अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। जैसा कि ए-2 के संबंध में है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयान का हवाला देते हुए, यह अतिरिक्त रूप से तर्क दिया गया था कि उसने केवल कार में लिफ्ट ली थी और, इस तरह, उसे होश में नहीं माना जा सकता। प्रतिबंधित पदार्थ का कब्जा

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित कियाः

15 ग्राम का अंतर। वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में वजन का अधिक महत्व नहीं है। नमूना एक सामान्य वजन पैमाने द्वारा लिया गया था और वजन एक किराये की दुकान, में पाया गया था जबकि प्रयोंगशाला में वजन सटीक पैमाने के साथ दर्ज किया गया था। यह इस बात से स्पष्ट होगा कि प्रयोगशाला में दर्ज नमूने का वजन 65.5606 ग्राम था। सर्वविदित है कि किराना दुकान में रखा तराजू और बाट ऐसे मानक के नहीं होते जो बहुत सटीकता से वस्तुओं का वजन कर सकें। इस पृष्ठभूमि में, वजन में छोटा अंतर अपना महत्व खो देता है, जब किसी को अभियोजन कहानी के दूसरे भाग में कोई कमजोरी नहीं मिलती है। [पैरा 11] [607-ई-एच; 608-ए]

राजेश जगदम्बा अवस्थी बनाम गोवा राज्य 2005 (9) एस.सी.सी. 773; दिलीप और एक अन्य बनाम एम.पी. राज्य, 2006 (9) पूरक। एससीआर 390=2007 (1) एससीसी 45 विशिष्ट।

नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2008 (10) एससीआर 379 = 2008 (16) एससीसी 417-संदर्भित।

2.1 धारा 50 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह तभी लागू होता जब वाहन आदि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की तलाशी ली जाती है। तत्काल मामले में, वाहन की तलाशी ली गई और वाहन से 'चरस' बरामद किया गया और अपीलार्थियों की तलाशी नहीं ली गई। चूंकि बरामदगी वाहन से हुई है इसलिए अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपीलकर्ताओं की तलाशी उस स्थान पर नहीं ली गई जहां वाहन को रोका गया था और तलाशी ली गई थी, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने और पुलिस स्टेशन आने के बाद, दर्ज करने से पहले उनके पास मौजूद वस्तुओं का पता लगाने के लिए उनकी तलाशी ली गई थी। उन्हें लॉक-अप में रखने से पहले। [पैरा 16 और 18] [611-जी-एच; 612-ए-बी; 611-बी-सी]

2.2 किसी अभियुक्त को चुनने का विकल्प तब दिया जाता है जब उसके पास चुनने का अधिकार हो। यह स्वीकार करने या अस्वीकार करने

के अधिकार का संचार है। इस मामले में, वाहन की पहली बार में ही तलाशी ली गई थी और इसलिए, अपीलकर्ताओं को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी के उनके अधिकार के बारे में सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना ही नहीं, विकल्प देकर अपीलकर्ताओं को उनके अधिकार से अवगत कराया गया और प्रकार, अधिनियम की धारा 50 का पूरी तरह से पालन किया गया था। [पैरा 18-19] [611-H; 612-A-B-E]

3.1 अपराध को अधिनियम की धारा 20 के दायरे में लाने के लिए, कब्जा सचेतन कब्जा होना चाहिए। अधिनियम की धारा 35 मानती है कि एक बार कब्ज़ा स्थापित हो जाने पर, अदालत यह मान सकती है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति खराब थी, जिसका अर्थ है, जानबूझकर कब्जा करना। इसके अलावा, जो व्यक्ति यह दावा करता है कि वह सचेत रूप से कब्जे में नहीं था उसे यह स्थापित करना होगा। सचेत कब्जे की धारणा अधिनियम की धारा 54 के तहत भी उपलब्ध है, जो यह प्रदान करती है कि आरोपी को अपराध करने के लिए माना जा सकता है जब तक कि वह तस्करी के कब्जे के लिए संतोषजनक ढंग से हिसाब नहीं दे दे। वर्तमान मामले में, दोनों अपीलकर्ताओं को उस कार में यात्रा करते हुए पाया गया जिसमें 'चरस' बरामद किया गया था और इसलिए, उनके पास वह कार थी। वे एक दूसरे को जानते थे। वे सार्वजनिक परिवहन वाहन में यात्रा नहीं कर रहे थे। सार्वजनिक परिवहन वाहन और निजी वाहन से यात्रा

करने वाले आरोपियों के बीच अंतर करना होगा। [पैरा 22] [613-जी-एच; 614-ए-बी; 613-एफ-जी]

3.2 सी.आर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान को अभियोजन के मामले की सत्यता या अन्यथा की सराहना करने के लिए ध्यान में रखा जाता है और यह एक सबूत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान शपथ दिलाए बिना दर्ज किए जाते हैं और उन बयानों के संदर्भ में आरोपी से जिरह् नहीं की जा सकती और इसलिए, उक्त कथन को साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 इस अर्थ में है कि तथापि जब कोई अभियुक्त अपने बचाव में गवाह के रूप् में उपस्थित होता है आरोपों का खण्डन करने पर उसके संस्करण का परीक्षण किया जाता है। जिरह् अपीलकर्ताओं ने ए-2 की याचिका का समर्थन करने के लिए किसी अन्य गवाह से पूछताछ करने का विकल्प नहीं चुना है। कार में लिफ्ट लेना और यदि कोई उपलब्ध न हो तो वे इसके संदर्भ में स्वयं का परीक्षण करने के लिए स्वतंत्र थे। धारा 315 दंड प्रक्रिया संहिता जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। अपराध बचाव का एक सक्षम गवाह है और हो सकता है। जो आरोपों के खण्डन में शपथ पर साक्ष्य दें। इसलिए, ए-2 की दलील कि उसने कार में लिफ्ट ली थी, केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं के बयानों के आधार पर स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है। [पैरा 21] [613 ए-ई]

मदन लाल और अन्य बनाम। एच.पी. राज्य, 2003 (2) पूरक। एस. सी. आर. 716 = 2003 (7) एस.सी.सी. 465-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भः

2008 (10) एससीआर 379 संदर्भित किया गया है	पैरा 9
2005 (9) एस.सी.सी. 773 प्रतिष्ठित	पैरा 10
2006 (9) पूरक। एस.सी.आर. 390 प्रतिष्ठित	पैरा 15
2003 (2) पूरक। एस.सी.आर. 716 भरोसा किया	पैरा 22

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील 1215/2005

उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 18.10.2004 से हिमाचल प्रदेश न्यायालय, शिमला अपील संख्या अपील सं. 603/2003 से, के साथ सीआरएल। ए.सं. 1216/2005

पी.एस. मिश्रा, नागेंद्र राय, जे.एस. भसीन, डी.के. पांडे, उपेंद्र मिश्रा, टी. महिपाल, शांतनु सागर, स्मारहर सिंह, जे.एस. भसीन, एस.चंद्र शेखर, नरेश के. शर्मा पक्षकारों की ओंर से उपस्थित।

न्यायालय निर्णय चंद्रमौली के.आर. प्रसाद, जे. द्वारा दिया गया था।

1. दोनों अपीलें एक ही निर्णय से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार उन्हें एक साथ सुना गया और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

2. अभियोजन पक्ष द्वारा सामने आया और दोनों अदालतों यानी ट्रायल और अपीलीय अदालत द्वारा स्वीकार किया गया मामला यह है कि 18 अक्टूबर, 2002 को सुबह 9.20 बजे पीडब्लू.16, ब्रिजेश सूद, स्टेशन हाउस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन सुंदरनगर, पीडब्लू.8, मदन के साथ लाल, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मी मंडी जिले के सुंदरनगर में ललित चौक पर नियमित जांच के लिए मौजूद थे। ब्रिजेश सूद को गुप्त सूचना मिली कि एक कार पंजीकरण संख्या एचपी-34-7700 मंडी की ओर से आ रही है जिसमें दो व्यक्ति भारी मात्रा में चरस लेकर जा रहे हैं। उपरोक्त सूचना को लिखित रूप दिया गया तथा उक्त आशय की सूचना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मण्डी को भेजी गई। सुबह लगभग 10 बजे, एक मारुति एस्टीम कार जिसका पंजीकरण नंबर HP-34-7700 है, मंडी की ओर से आई, जिसे PW.16, ब्रिजेश सूद ने रोका और उसने कार में चालक सहित दो व्यक्तियों को बैठे पाया। ब्रिजेश सूद ने कार चला रहे व्यक्ति से पूछताछ की और उसने अपना नाम देहल सिंह (2005 की आपराधिक अपील संख्या 1215 में अपीलकर्ता) बताया और दूसरा व्यक्ति ड्राइवर की सीट के बगल वाली अगली सीट पर बैठा था। उसका नाम दिनेश कुमार, निवासी गोवा (2005 की आपराधिक अपील संख्या 1216 में अपीलकर्ता) है। ब्रिजेश सूद ने आरोपी व्यक्तियों को लिखित में विकल्प दिया कि वे मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष वाहन की व्यक्तिगत तलाशी या तलाशी देना चाहते हैं या नहीं। दोनों अपीलकर्ताओं ने उसके द्वारा खोजे

जाने के लिए अपनी सहमति दी। PW.16 के अनुसार, ब्रिजेश सूद ने कार और कार के अंदर पड़े सामान की तलाशी ली, लेकिन कार या सामान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। पीडब्लू.3, चुरामणि द्वारा एक मैकेनिक को बुलाया गया, जिसने खिड़कियों/दरवाज़ों की ढालें खोलीं जब ढालों और दरवाजों के बीच काले और लाल चिपकने वाले टेप से लिपटे भूरे रंग के पैकेट छिपे हुए पाए गए। पैकेट खोलने पर छड़ी और चपाती के आकार में चरस निकली। चुरामणि को पीडब्लू.16, ब्रिजेश सूद ने तराजू और वजन लाने के लिए कहा था। वह पीडब्लू.5, राम लाल की किराने की दुकान से वजन का तराजू लेकर आया और वजन पर 27 किग्रा. 800 ग्राम. की चरस बरामद हुई. पूरी चरस को मिलाकर 50-50 ग्राम के दो सैंपल निकाले गए। इसे विधिवत सील कर दिया गया।

3. अपीलकर्ता, देहल सिंह ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन से संबंधित अन्य कागजात के साथ पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। अपीलकर्ताओं और जब्त चरस को नमूनों के साथ पुलिस स्टेशन ले जाया गया जहां अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत तलाशी ली गई। अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत तलाशी से बरामद चरस और अन्य वस्तुओं के नमूने सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पीडब्लू.8, अतिरिक्त मालखाना हेड कांस्टेबल, राजिंदर कुमार के पास जमा कर दिए गए। इसके बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई और एक विशेष रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी गई। पीडब्लू.8, राजिंदर कुमार ने नमूने का एक पार्सल रासायनिक परीक्षक को भेजा, जिसने अपनी रिपोर्ट में

कहा कि इसमें चरस था। सामान्य जांच के बाद दोनों अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया और अंततः उन पर मुकदमा चलाया गया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और उन पर मुकदमा चलाए जाने का दावा किया।

4. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में कुल मिलाकर 16 गवाहों की जांच की है, इसके अलावा कई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर लाए गए हैं। अपने बयानों में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ताओं ने गलत आरोप लगाने की दलील दी और दोनों ने कहा कि अपीलकर्ता, दिनेश कुमार ने कुल्लू से दिल्ली तक कार में लिफ्ट ली थी।

5. सबूतों की सराहना करने पर ट्रायल कोर्ट ने दोनों अपीलकर्ताओं को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और 1 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई।,00,000/- प्रत्येक और जुर्माना अदा न करने पर चार साल की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा।

6. अपीलकर्ताओं ने दोषसिद्धि और सजा के फैसले और आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील की और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने

18 अक्टूबर, 2004 को आपराधिक अपील संख्या 600 और 603, 2003 में पारित अपने सामान्य निर्णय द्वारा दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।

7. दोनों अपीलकर्ता अपील के लिए विशेष अनुमति देकर उपरोक्त आदेश का विरोध करते हैं।

8. 2005 की आपराधिक अपील संख्या 1215 में अपीलकर्ता की ओर से श्री नागेंद्र राय, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित होते हैं, जबकि 2005 की आपराधिक अपील संख्या 1216 में अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व विद्वान वरिष्ठ वकील श्री पीएस मिश्रा द्वारा किया जाता है।

9. श्री राय का कथन है कि अभियोजन के अनुसार 50 ग्राम के दो नमूने। प्रत्येक को लिया गया और जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया, लेकिन प्रयोगशाला में प्राप्त नमूने का शुद्ध वजन 65.5606 ग्राम था। श्री राय के कथन के अनुसार, नमूने के वजन में यह विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करती है और यह अभियोजन के मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि यदि विश्लेषक द्वारा पाई गई मात्रा सीलबंद और उसे भेजी गई मात्रा से अधिक है तो वसूली कार्यवाही की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। वह बताते हैं कि जब नमूने लिए गए थे उस समय और प्रयोगशाला में उनके वजन में विसंगति को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने नूर आगा बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2008(16)

एससीसी 417 के मामले में, अभियोजन पक्ष के मामले को भरोसेमंद नहीं माना। हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 97 की ओर आकर्षित किया गया है जो इस प्रकार है:

"97. इन नमूनों का भाग्य विवादित नहीं है। हालांकि उनमें से दो को थोक के साथ मालखाने में रखा गया था, लेकिन उत्पादित नहीं किया गया था। इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जहां तक तीसरे नमूने की बात है, जो कथित तौर पर था केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, नई दिल्ली को भेजे गए संबंध में, यह स्वीकार किया गया है कि उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य में विसंगतियां अदालत के सामने आई हैं, अर्थात्ः

(i) जबकि नमूने का मूल वजन 5 ग्राम था, जैसा कि एक्स्ट्स से पता चलता है। पीबी, पीसी और एक्सटेंशन के साथ संलग्न पत्र। प्रयोगशाला में नमूने का वजन पीएच 8.7 ग्राम दर्ज किया गया।

(ii) प्रारंभ में, दर्ज किए गए नमूने का रंग भूरा था, लेकिन रासायनिक-परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पाउडर का रंग सफेद दर्ज किया गया था।"

(हमारा रेखांकित करते हुए)

10. राजेश जगदंबा अवस्थी बनाम गोवा राज्य, 2005 ¼9) एससीसी 733 के मामले में भी इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया

गया है, और हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 14 पर आकर्षित किया गया है जो इस प्रकार है:

> "14. हमें उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को बरकरार रखना संभव नहीं लगता। अपीलकर्ता पर 180.70 ग्राम वजन वाली चरस पाए जाने का आरोप लगाया गया था। उसके पास से बरामद चरस को दो लिफाफों में पैक और सील कर दिया गया था। जब कहा गया कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, पीडब्लू 1 द्वारा प्रयोगशाला में लिफाफे खोले गए, तो उन्हें मात्रा अलग-अलग मिली। जबकि एक लिफाफे में अंतर केवल न्यूनतम था, दूसरे में वजन में महत्वपूर्ण अंतर था। उच्च न्यायालय ने स्वयं पाया कि यह इसे मात्र एक छोटी सी विसंगति के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने हमारे समक्ष सही ही प्रस्तुत किया कि लिफाफा बी में पाए गए चरस की मात्रा को नजरअंदाज करते हुए केवल लिफाफे ए से जो बरामद किया गया था, उसके आधार पर अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल एक ही तलाशी और जब्ती हुई थी, और अपीलकर्ता से जो कुछ भी बरामद किया गया था वह दो लिफाफों में पैक किया गया था। वसूली कार्यवाही की

विश्वसनीयता काफी हद तक खत्म हो गई है यदि यह पाया जाता है कि पीडब्लू 1 द्वारा वास्तव में पाई गई मात्रा कम थी मात्रा को सील कर उनके पास भेज दिया गया। जैसा कि उन्होंने ठीक ही जोर दिया था, सवाल यह नहीं है कि कितना जब्त किया गया, बल्कि यह है कि क्या वास्तविक जब्ती हुई थी, और क्या जो जब्त किया गया था वह वास्तव में रासायनिक विश्लेषण के लिए पीडब्लू 1 को भेजा गया था। अभियोजन पक्ष इस विसंगति को समझाने में सक्षम नहीं है और इसलिए, यह अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बना देता है।"

11. हमें श्री राय की दलील में कोई तथ्य नहीं मिला और जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया, वे स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। वाहन को हाईवे पर रोका गया और उसकी तलाशी ली गई और पीडब्लू.16, ब्रिजेश सूद के साक्ष्य में यह आया है कि उसने पीडब्लू.3, चुरामणि को पीडब्लू.5, राम लाल की किराने की दुकान से तराजू और बाट लाने के लिए भेजा था। पीडब्लू.3, चुरामणि और पीडब्लू.5, किराना दुकान के मालिक राम लाल के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि तराजू और वजन किराना दुकान से आया था। यह सामान्य ज्ञान है कि किराने की दुकान में रखा तराजू और वजन ऐसे मानक के नहीं हैं जो वस्तुओं को बहुत सटीकता से तौल सकें और इसलिए 15 ग्राम का अंतर होता है। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में

वजन का ज्यादा महत्व नहीं है। नमूना एक किराने की दुकान में पाए जाने वाले सामान्य तराजू और वजन से लिया गया था, जबकि प्रयोगशाला में वजन को सटीक पैमाने के साथ दर्ज किया गया था। यह इस बात से स्पष्ट होगा कि प्रयोगशाला में दर्ज नमूने का वजन 65.5606 ग्राम था। इस पृष्ठभूमि में, वजन में छोटा अंतर अपना महत्व खो देता है, जब किसी को अभियोजन कहानी के दूसरे भाग में कोई कमजोरी नहीं मिलती है।

12. अब नूर आगा (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए नमूने लेते समय और प्रयोगशाला में वजन में अंतर को महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि उक्त मामले में नमूना कस्टम अधिकारियों द्वारा लिया गया था। हवाई अड्डे पर और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वजन एक सटीक पैमाने से लिया गया था। इसके अलावा, यह न केवल वजन में विसंगति है जिसके कारण इस न्यायालय ने अभियोजन के मामले को खारिज कर दिया, बल्कि उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कई अन्य विसंगतियों पर भी विचार किया। यह निर्णय के पैराग्राफ 98 से स्पष्ट होगा, जो इस प्रकार है:

> "98. हम इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हैं कि नमूने के वजन में मामूली अंतर को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है कि पूरे अभियोजन मामले को नजरअंदाज कर दिया जाए क्योंकि आम तौर पर सार्वजनिक स्थान पर एक

अधिकारी एक अच्छा पैमाना नहीं ले जाएगा। उसके साथ। यहाँ, हालाँकि, परिदृश्य अलग है। जब्ती का स्थान एक हवाई अड्डा था। तलाशी और जब्ती करने वाले अधिकारी सीमा शुल्क विभाग से थे। उनके पास मात्रा में मामूली वृद्धि या कमी के रूप में अच्छे पैमाने होने चाहिए आयातित वस्तुओं की कीमत चाहे प्रतिबंधित हो या अन्यथा, सीमा शुल्क अधिनियम के तहत एक बड़ा अंतर हो सकता है।"

13. इसके अलावा उक्त मामले में यह देखा गया है कि व्यक्तिगत रूप से वजन में विसंगति घातक नहीं हो सकती है। इस संबंध में उक्त निर्णय के पैराग्राफ 119 (3) और (4) को पुन: प्रस्तुत करना उपयुक्त है:

119. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

1. xxx xxx xxx xxx

2. xxx xxx xxx xxx

3. भौतिक साक्ष्यों के निस्तारण एवं निपटारे में बड़ी संख्या में विसंगतियां हैं। सरकारी गवाहों के बयानों में विरोधाभास है. स्वतंत्र गवाहों की जांच न करने और स्वीकारोक्ति की प्रकृति और ऐसी स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग की परिस्थितियों से अपीलकर्ता के अपराध का निष्कर्ष नहीं निकलता है।

4. विसंगतियों पर निष्कर्ष निकालना, हालांकि यदि व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है, तो अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं हो सकता है, लेकिन यदि परिदृश्य का संचयी दृष्टिकोण लिया जाता है, तो अभियोजन पक्ष के मामले में विश्वसनीयता की कमी होनी चाहिए।

5. xxx xxx xxx xxx

6. xxx xxx xxx xxx"

14. अब, हम राजेश जगदंबा अवस्थी (सुप्रा) के मामले में अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए इस न्यायालय के फैसले पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसे स्पष्ट रूप से अलग पाते हैं। उक्त मामले में वास्तव में न्यायालय ने बरामदगी की कार्यवाही को संदिग्ध पाया और इसके अलावा जब्त किए गए पदार्थ के साथ छेड़छाड़ की भी पूरी संभावना थी। उन कमज़ोरियों के कारण इस न्यायालय को अभियोजन मामले की सत्यता पर संदेह हुआ। यह निर्णय के पैराग्राफ 15 से स्पष्ट है जो इस प्रकार है:

> "15. इतना ही नहीं। पीडब्लू 4 के साक्ष्य से हमें पता चलता है कि उसने पीएसआई थोराट से सील ले ली थी और जब्ती रिपोर्ट, पंचनामा आदि तैयार करने के बाद दोनों पैकेटों को पुलिस स्टेशन ले गया और पैकेटों को सौंप दिया। साथ ही निरीक्षक यादव को मुहर लगा दी। उनके अनुसार

अगले दिन, उन्होंने पुलिस स्टेशन से पैकेट वापस ले लिए और उन्हें अपराध शाखा में वैज्ञानिक सहायक पीडब्लू 3 मनोहर जोशी के पास भेज दिया, जिन्होंने इसे पीडब्लू 1 को भेज दिया। रासायनिक विश्लेषण। इन परिस्थितियों में, इस तर्क का औचित्य है कि चूंकि सील और पैकेट एक ही व्यक्ति की हिरासत में थे, इसलिए जब्त किए गए पदार्थ के साथ छेड़छाड़ की पूरी संभावना थी, और यही एकमात्र परिकल्पना है जिससे वजन में विसंगति को समझाया जा सके। मामले के तथ्यों के बारे में कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष के मामले की सत्यता पर गंभीर संदेह है।"

15. श्री राय का कहना है कि यद्यपि अपीलकर्ता को राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्हें उनकी उपस्थिति में तलाशी लेने के उनके अधिकार से अवगत नहीं कराया गया था और इसलिए अपनाई गई प्रक्रिया आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 50 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनकी उपस्थिति में तलाशी लेने के उसके

अधिकार से अवगत कराया जाना चाहिए। उनके अनुसार विकल्प बताना और अधिकार से अवगत कराना अलग-अलग हैं। उनके अनुसार, यह अधिनियम की धारा 50 के आदेश को पूरा नहीं करता है और एक बार इसका उल्लंघन स्थापित हो जाने पर तलाशी और जब्ती अवैध हो जाती है और अकेले इस आधार पर अपीलकर्ताओं की सजा रद्द हो जाती है। वह बताते हैं कि चरस अपीलकर्ताओं के कब्जे से नहीं बल्कि वाहन से बरामद किया गया था, लेकिन फिर भी अपीलकर्ताओं की भी तलाशी ली गई और इस प्रकार अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य था। उन्हें दिलीप और अन्य बनाम एमपी राज्य 2007 ¼41½ एससीसी 450 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से उपरोक्त कथन का समर्थन मिलता है, और हमारा ध्यान फैसले के पैराग्राफ 16 की ओर आकर्षित हुआ है जो इस प्रकार है:

> "16. इस मामले में, जहां तक स्कूटर की तलाशी का सवाल है, धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं के व्यक्ति की भी तलाशी ली गई थी, यह अनिवार्य था पीडब्लू 10 की ओर से उक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए। ऐसा नहीं किया गया।"

16. श्री राय का यह निवेदन हमारे लिये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है। वर्तमान मामले में वाहन की तलाशी ली गई और वाहन से चरस बरामद की गई और अपीलकर्ताओं के व्यक्तियों की तलाशी नहीं ली गई। चूँकि बरामदगी वाहन से हुई है, हमारी राय में, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान का अनुपालन करना आवश्यक नहीं था। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि अपीलकर्ताओं की तलाशी उस स्थान पर नहीं की गई जहां वाहन को रोका गया था और तलाशी ली गई थी, बल्कि उन्हें गिरफ्तार करने और पुलिस स्टेशन लाने के बाद, उन्हें थाने में रखने से पहले उनके पास मौजूद वस्तुओं का पता लगाने के लिए उनकी तलाशी ली गई थी। हवालात।

17. इतना ही नहीं अभियोजन पक्ष ने अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन का भी दावा किया है. अधिनियम की धारा 50(1), जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:-

50. शर्तें जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी। (1) जब धारा 42 के तहत विधिवत अधिकृत कोई अधिकारी धारा 42 या धारा 43 के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तो वह, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी लेगा। व्यक्ति अनावश्यक विलंब के बिना उल्लिखित किसी भी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी के पास जा सकता है

धारा 42 में या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास।

xxx xxx xxx xxx

18. उपरोक्त प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह तभी लागू होता है जब वाहन आदि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की तलाशी ली जाती है। इसके अलावा प्राधिकृत अधिकारी को तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने के लिए सूचित करना होता है, यदि तलाशी लिए जाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता हो। ऐसा विकल्प अपीलकर्ताओं को दिया गया था और, हमारी राय में, यह उन्हें उनके अधिकार से अवगत कराने के अलावा और कुछ नहीं है। किसी अभियुक्त को चुनने का विकल्प तभी दिया जाता है जब उसके पास चुनने का अधिकार हो। यह स्वीकार करने या अस्वीकार करने के अधिकार का संचार है। इसलिए, हमारी राय में, अपीलकर्ताओं को तलाशी का विकल्प देने से अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता पूरी होती है। अपीलकर्ताओं द्वारा भरोसा किए गए दिलीप (सुप्रा) के मामले में जो प्रश्न विचार के लिए आया वह यह था कि क्या अधिनियम की धारा 50 का अनुपालन करना आवश्यक है और इस तथ्य की पृष्ठभूमि में कि तलाशी और जब्ती से पहले स्कूटर से प्रतिबंधित सामग्री, अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली गई, इस न्यायालय ने माना कि यह आवश्यक था। यह निर्णय के पैराग्राफ 12 से स्पष्ट होगा जो इस प्रकार है:

"12. स्कूटर से प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने से पहले, अपीलकर्ताओं की व्यक्तिगत तलाशी ली गई थी और, माना जाता है कि उस समय भी, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का, हालांकि कानून में आवश्यक था, अनुपालन नहीं किया गया था।"

19. वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले देखा गया था, वाहन की तलाशी पहली बार में की गई थी और इसलिए अपीलकर्ताओं को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी के उनके अधिकार के बारे में सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, हमने पाया है कि विकल्प देने से अपीलकर्ताओं को उनके अधिकार से अवगत कराया गया और इसलिए अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान का पूरी तरह से पालन किया गया।

20. श्री पीएस मिश्रा ने श्री राय के निवेदन को स्वीकार करते हुए एक अतिरिक्त निवेदन किया है। उनका तर्क है कि अपीलकर्ता दिनेश कुमार को चरस के जानबूझकर कब्जे में नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने वाहन में लिफ्ट ली थी और उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि चरस को वाहन में ले जाया जा रहा था। इस संबंध में उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अपीलकर्ताओं के बयानों का हवाला दिया था। इन दोनों ने विशेष रूप से दलील दी थी कि इस अपीलकर्ता ने कार में

लिफ्ट ली थी। श्री मिश्र के अनुसार यदि यह स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया जाये तो यह अपीलकर्ता बरी किये जाने योग्य है।

21. हमें श्री मिश्र के इस निवेदन में कोई तथ्य नहीं मिला। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान को अभियोजन के मामले की सत्यता या अन्यथा की सराहना करने के लिए ध्यान में रखा जाता है और यह एक सबूत नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत एक अभियुक्त का बयान शपथ दिलाए बिना दर्ज किया जाता है और इसलिए, उक्त बयान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ताओं ने इस दलील का समर्थन करने के लिए किसी अन्य गवाह की जांच करने का विकल्प नहीं चुना है और यदि कोई भी उपलब्ध नहीं है तो वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के संदर्भ में खुद की जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि किसी अपराध का आरोपी व्यक्ति बचाव पक्ष का एक सक्षम गवाह और आरोपों के खंडन में शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान को साक्ष्य के रूप में न मानने का कारण है क्योंकि उन बयानों के संदर्भ में अभियुक्त से जिरह नहीं की जा सकती है। हालाँकि, जब कोई आरोपी आरोप को गलत साबित करने के लिए बचाव में गवाह के रूप में पेश होता है, तो उसके कथन का परीक्षण उसकी जिरह द्वारा किया जा सकता है। इसलिए, हमारी राय में अपीलकर्ता दिनेश कुमार की यह दलील कि उसने कार में

लिफ्ट ली थी, केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के बयानों के आधार पर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

22. दोनों अपीलकर्ताओं को उस कार में यात्रा करते हुए पाया गया है जिससे चरस बरामद की गई थी और इसलिए, उनके पास वह कार थी। वे एक दूसरे को जान रहे थे. वे सार्वजनिक परिवहन वाहन में यात्रा नहीं कर रहे थे। सार्वजनिक परिवहन वाहन और निजी वाहन से यात्रा करने वाले आरोपियों के बीच अंतर करना होगा। इस बात पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अपराध को अधिनियम की धारा 20 के दायरे में लाने के लिए कब्जे को सचेतन कब्जे में रखना होगा। अधिनियम की धारा 35 मानती है कि एक बार कब्ज़ा स्थापित हो जाने पर न्यायालय यह मान सकता है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति ख़राब थी, जिसका अर्थ जानबूझकर कब्ज़ा करना है। इसके अलावा जो व्यक्ति यह दावा करता है कि वह सचेत रूप से कब्जे में नहीं था, उसे इसे स्थापित करना होगा। सचेत कब्जे की धारणा अधिनियम की धारा 54 के तहत भी उपलब्ध है, जो यह प्रदान करती है कि अभियुक्त को अपराध करने के लिए माना जा सकता है जब तक कि वह संतोषजनक ढंग से प्रतिबंधित सामग्री के कब्जे का विवरण नहीं देता। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे मदन लाल और अन्य बनाम एचपी राज्य, 2003 (7) एससीसी 465 के मामले में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है, जिसमें इसे इस प्रकार रखा गया है:

"26. एक बार कब्ज़ा स्थापित हो जाने के बाद, जो व्यक्ति दावा करता है कि यह एक सचेत कब्ज़ा नहीं था, उसे इसे स्थापित करना होगा, क्योंकि उसका कब्ज़ा कैसे हुआ यह उसके विशेष ज्ञान में है। अधिनियम की धारा 35 इस स्थिति को वैधानिक मान्यता देती है कानून में उपलब्ध अनुमान के कारण। धारा 54 के संदर्भ में भी यही स्थिति है, जहां अवैध वस्तुओं के कब्जे से भी अनुमान निकाला जा सकता है।

27. वर्तमान मामले के तथ्यात्मक परिदृश्य में, न केवल कब्ज़ा बल्कि सचेत कब्ज़ा स्थापित किया गया है। अभियुक्त-अपीलकर्ताओं द्वारा यह नहीं दिखाया गया है कि कब्जा अधिनियम की धारा 35 और 54 की तार्किक पृष्ठभूमि में सचेत नहीं था।"

23. इस प्रकार हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती और तदनुसार इन्हें खारिज किया जाता है।

आर.पी.

अपील खारिज की गई

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीपेन्द्र कुमार मीणा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

उड़ीसा में गुजरात उच्च न्यायालय के अपील संख्या 9958/2001 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 05.08.2008 से उत्पन्न।